NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 4-03-2025

विषय सूची

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (C-3) प्रारंभ
पूँजी खाता परिवर्तनीयता
भारत में निर्धनता का अनुमान
IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
बोस धातु

संक्षिप्त समाचार

भारत को जाम्बिया में तांबा अन्वेषण ब्लॉक मिला
स्वावलंबिनी
समानता का सिद्धांत
अमेरिका ने क्रिप्टो रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की घोषणा की
फेरिहाइड्राइट
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
भारत में नदी डॉल्फ़िन का प्रथम व्यापक अनुमान
ऑस्कर

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (C-3) प्रारंभ

संदर्भ

- हाल ही में, भारत ने जयपुर में आयोजित एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के दौरान शहर के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बहु-राष्ट्रीय गठबंधन, सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी (C-3) का शुभारंभ किया है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- भारत के प्रधानमंत्री ने प्रो-प्लैनेट पीपुल (P3) दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और सतत् शहरी विकास के लिए 3R (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल) के महत्त्व पर बल दिया।
- CITIIS 2.0 (नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहर निवेश) के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - इसमें 1,800 करोड़ रुपये के समझौते शामिल हैं, जिससे 14 राज्यों के 18 शहरों को लाभ होगा और यह अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए प्रकाश स्तंभ परियोजनाओं के रूप में कार्य करेगा।

पृष्ठभूमि

About Circular Economy

- It is an economic model that **focuses on sustainability** by emphasizing reuse, recycling, and regeneration of materials.
- It helps reduce environmental degradation, promotes resource efficiency, and supports long-term economic growth.

Key Principles

- Design for Sustainability;
- Waste Reduction & Recycling;
- Efficient Resource Use;
- Regeneration of Natural Systems;

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत 2009 में की गई थी, जिसका उद्देश्य तेजी से शहरीकृत एवं औद्योगिक होते एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत् अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों के लिए क्षेत्रीय सहयोग करना था।
- हनोई 3R घोषणापत्र (2013-2023) में अधिक संसाधन कुशल और परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई है।
- यह 'वैश्विक प्लास्टिक संधि' के लिए सक्रिय रूप से वार्तालाप कर रहा है।

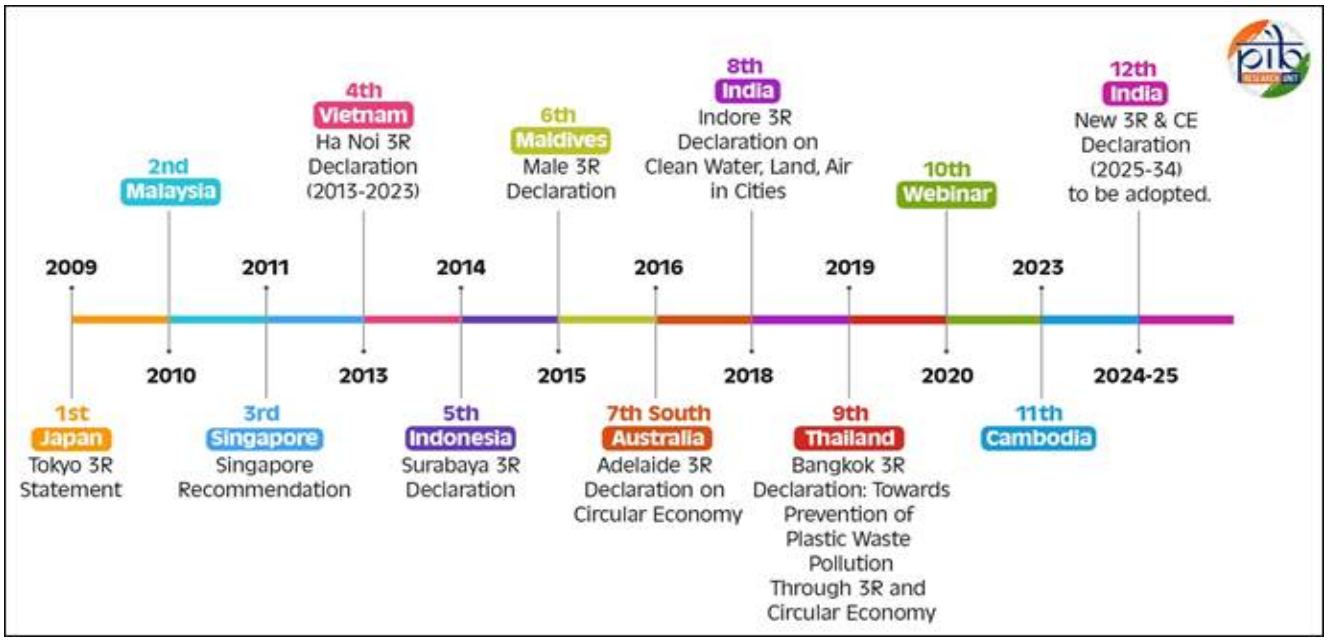

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (C3)

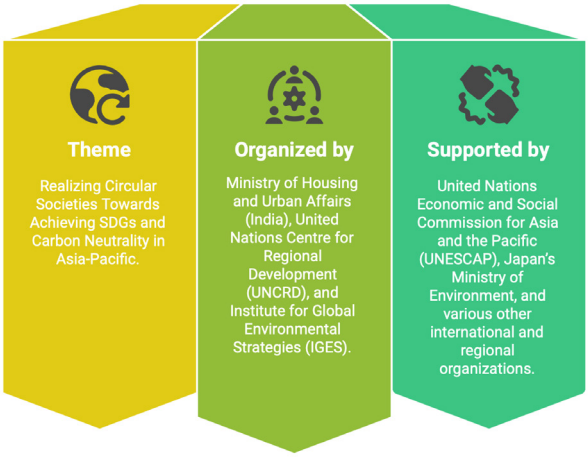

- **परिचय:** यह एक बहु-राष्ट्रीय गठबंधन है जिसे शहरी नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन उपयोग में सतत् प्रथाओं को एकीकृत करके शहरी केंद्रों को परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **उद्देश्य:** पृथक्करण, खाद बनाने और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, पुनः उपयोग और साझा सामग्रियों को बढ़ावा देकर संसाधन दक्षता को बढ़ाने एवं सतत् बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

शहरी स्थिरता के लिए C3 का महत्त्व

- **जलवायु परिवर्तन को कम करना:** अपशिष्ट को कम करके और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके, C3 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है।
- **आर्थिक लाभ:** एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संक्रमण से रीसाइक्लिंग, पुनः निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसर सृजित हो सकते हैं।
- **लोचशील शहर:** एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि शहर सीमित संसाधनों पर कम निर्भर हो जाएँ, जिससे वे आपूर्ति शृंखला व्यवधानों और आर्थिक मंदी के लिए अधिक लचीले बन सकें।
- **रोज़गार सृजन:** यह अक्षय ऊर्जा, सतत् निर्माण और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद निर्माण जैसे क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करता है।
- **जीवन की बेहतर गुणवत्ता:** स्वच्छ वातावरण, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और हरित शहरी स्थान बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ

- विश्व भर के कई शहरों जैसे कि एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन और टोक्यो ने पहले ही C3 ढाँचे के तहत सर्कुलर इकोनॉमी नीतियों को लागू कर दिया है।
- **भारत में, सर्कुलरिटी निम्नलिखित पहलों के माध्यम से गति पकड़ रही है:**
  - **स्वच्छ भारत मिशन:** अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना।
  - **स्मार्ट सिटी मिशन:** सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देना।
  - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** कंपनियों को उनके उत्पादों के जीवनचक्र के लिए जवाबदेह बनाना।
  - **गोबर-धन योजना:** वर्तमान में भारत के कुल जिलों में से 67.8% को कवर करती है।

शहरों में सर्कुलरिटी को लागू करने में चुनौतियाँ

- जागरूकता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
- उच्च प्रारंभिक निवेश लागत।
- व्यवसायों और उपभोक्ताओं की ओर से परिवर्तन का प्रतिरोध।
- अपर्याप्त नीति समर्थन और प्रवर्तन तंत्र।

आगे की राह

- ऐसी नीतियों का विकास और क्रियान्वयन करना जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अनिवार्य बनाती हों।
- सतत् सामग्रियों और प्रक्रियाओं के लिए अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना।
- सर्कुलर जीवन शैली के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना।
- सर्कुलर अर्थव्यवस्था परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना।

Source: TH

पूँजी खाता परिवर्तनीयता

संदर्भ

- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत को वर्तमान प्रति व्यक्ति आय स्तर पर पूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता की ओर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता (CAC)

- पूँजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से विदेशी में और इसके विपरीत परिवर्तित करना है।
- यह विदेशी निवेश, परिसंपत्ति खरीद और धन प्रेषण के लिए अप्रतिबंधित पूँजी प्रवाह की अनुमति देता है।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता की वर्तमान स्थिति

- भारत आंशिक पूँजी खाता परिवर्तनीयता व्यवस्था का पालन करता है।
- जबकि चालू खाता लेनदेन (जैसे वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार) पूरी तरह से परिवर्तनीय हैं, पूँजी खाता लेनदेन विनियमित हैं।
- भारत के पूँजी खाता ढाँचे के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं;
  - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अत्यंत सीमा तक उदारीकृत है, लेकिन अभी भी संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय सीमाओं और सरकारी अनुमोदन के अधीन है।
  - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को कुछ क्षेत्रों में स्वामित्व सीमाओं पर प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।
  - भारतीय निवासियों द्वारा बाहरी निवेश की अनुमति है, लेकिन उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अन्दर।

पूर्ण CAC के लाभ

- **अधिक पूँजी प्रवाह:** मुक्त पूँजी प्रवाह अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, जिससे आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण:** वित्तीय एकीकरण में वृद्धि से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुँच बढ़ती है।
- **बेहतर क्रेडिट रेटिंग:** अधिक खुला पूँजी खाता आर्थिक परिपक्वता और स्थिरता का संकेत दे सकता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

पूर्ण CAC की चुनौतियाँ

- **वृहद आर्थिक अस्थिरता:** अप्रतिबंधित पूँजी प्रवाह विनिमय दरों और मुद्रास्फीति में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।
- **पूँजी पलायन का जोखिम:** आर्थिक अनिश्चितता के समय में, पूँजी का तेजी से बहिर्गमन वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर सकता है।
- **बाहरी झटकों के प्रति जोखिम:** खुले पूँजी खाते अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकटों और अचानक पूँजी परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
- **बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियाँ:** एक पूरी तरह से परिवर्तनीय पूँजी खाते के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के बिना बाहरी आघातों को संभालने में सक्षम हो।

तारापोरे समिति की सिफारिशें

- **राजकोषीय समेकन:** व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3-3.5% के आसपास बनाए रखना।
- **मौद्रिक नीति के उद्देश्य:** मुद्रास्फीति दरों को वैश्विक स्तरों के अनुरूप बनाना और यह सुनिश्चित करना कि ब्याज दरें मुद्रास्फीति के अंतर को प्रतिबिंबित करना।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** बेहतर निर्णय लेने के लिए मौद्रिक नीति ढाँचे को बढ़ाना।
- **बैंकिंग प्रणाली सुधार:** उदार पूँजी प्रवाह के लिए पुनर्गठन, सुरक्षा उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से बैंकों को मजबूत बनाना।

- **भंडार की पर्याप्तता:** पूर्ण CAC के कार्यान्वयन के साथ, बाहरी झटकों को अवशोषित करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को मापने में भंडार की पर्याप्तता एक महत्त्वपूर्ण मानक होगी।

निष्कर्ष

- यद्यपि पूँजी खाता परिवर्तनीयता संभावित लाभ प्रदान करती है, भारत को अपनी आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर समय से पहले बदलाव अर्थव्यवस्था को वित्तीय अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार, विनिमय दर स्थिरता और व्यापक आर्थिक लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक अच्छी तरह से संतुलित रणनीति अधिक पूँजी खाता खुलेपन की दिशा में सही राह निर्धारित करने में आवश्यक होगी।

Source: TH

भारत में निर्धनता का अनुमान

संदर्भ

- अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन के एक अध्ययन के अनुसार, विगत् दशक में भारत में निर्धनता एवं असमानता में भारी कमी आई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह अध्ययन 2022-23 और 2023-24 के सरकारी घरेलू व्यय डेटा पर आधारित है।
- **निर्धनता में कमी:** $3.65 PPP लाइन पर भारत की निर्धनता दर 2011-12 में 52% से घटकर 2023-24 में 15.1% हो गई। $1.90 PPP लाइन पर अत्यधिक निर्धनता अब 1% से नीचे है।
- **उपभोग वृद्धि:** जनसंख्या के निचले तीन दशमलवों में खपत में सबसे बड़ा सुधार देखा गया, जो रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाता है।
- **घटती असमानता:** उपभोग असमानता में कमी आई है, गिनी गुणांक 2011-12 में 37.5 से घटकर 2023-24 में 29.1 हो गया है।
- **वैश्विक संदर्भ:** भारत की असमानता में कमी एक बड़ी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए असाधारण है, केवल भूटान और डोमिनिकन गणराज्य (छोटी जनसंख्या के साथ) के पास बेहतर रिकॉर्ड हैं।
- **नई गरीबी रेखा की आवश्यकता:** वर्तमान गरीबी रेखाएँ पुरानी हो चुकी हैं, जो यूरोप की तरह निचले 33वें प्रतिशत या सापेक्ष निर्धनता के उपायों पर आधारित एक नए बेंचमार्क का सुझाव देती हैं।
  - नीति आयोग ने अभी तक आधिकारिक निर्धनता अनुमानों को संशोधित नहीं किया है, जिन्हें पिछली बार तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने निर्धारित किया था।

भारत में गरीबी रेखा का अनुमान

- **तेंदुलकर समिति (2009):** सुरेश तेंदुलकर पद्धति में गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ₹33 और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन ₹27 का व्यय थी।
  - 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी।
- **रंगराजन समिति (2014):** रंगराजन पद्धति में, शहरी क्षेत्रों में यह 47 रुपये प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 रुपये प्रति दिन थी।
  - सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए, तेंदुलकर गरीबी रेखा का उपयोग करके निर्धनता को मापा जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा:** विश्व बैंक किसी व्यक्ति को अत्यंत गरीब के रूप में परिभाषित करता है यदि वह प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहा है, जिसे मुद्रास्फीति के साथ-साथ देशों के बीच मूल्य अंतर के लिए समायोजित किया जाता है।

भारत में गरीबी रेखा की गणना से संबंधित चिंताएँ

- **अपर्याप्त सीमा:** 965 रुपये (शहरी) और 781 रुपये (ग्रामीण) प्रति माह की अद्यतन गरीबी रेखा को बुनियादी

जीवन स्तर को दर्शाने के लिए बहुत कम माना जाता है, जिससे निर्धनता को सही ढंग से न दर्शाने के लिए आलोचना होती है।

- **पुरानी पद्धति:** यह कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित करती है और आधुनिक उपभोग पैटर्न एवं जरूरतों को दर्शाने में विफल रहती है।
- **गैर-खाद्य जरूरतों पर सीमित विचार:** गरीबी रेखा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं में बढ़ते निजी व्यय को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखती है।
- **राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय जीवन-यापन लागत अंतरों के बावजूद एक ही गरीबी रेखा सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती है, जो निर्धनता आकलन की सटीकता को विकृत करती है।
- **नियमित अपडेट की कमी:** आधिकारिक गरीबी रेखा को नई आर्थिक वास्तविकताओं, जैसे मुद्रास्फीति या उपभोग पैटर्न में बदलाव के साथ संरेखित करके अपडेट नहीं किया गया है, जिससे यह कम प्रासंगिक हो गई है।

आगे की राह

- वर्तमान आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति और बदलते उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए समय-समय पर गरीबी रेखा को संशोधित करना।
- **मापदंडों को व्यापक बनाएँ:** जीवन की वास्तविक लागत को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए गरीबी रेखा की गणना में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे गैर-खाद्य कारकों को शामिल करना।
- **क्षेत्रीय समायोजन:** राज्यों और क्षेत्रों में जीवन की लागत में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ लागू करना।
- **आधुनिक पद्धतियाँ अपनाएँ:** पुरानी कैलोरी-आधारित मापों से दूर हटें और पोषण संबंधी आवश्यकताओं और समग्र कल्याण जैसे अधिक समग्र संकेतकों को अपनाना।

Source: SJ

IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है, जिससे वे भारत में 25वें और 26वें नवरत्न CPSEs (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) बन गए हैं।

नवरत्न स्थिति के बारे में

- नवरत्न एक प्रतिष्ठित वर्गीकरण है जो उच्च प्रदर्शन करने वाले CPSE को दिया जाता है, जो उन्हें अधिक निवेश स्वायत्तता और परिचालन लचीलापन प्रदान करता है।
- वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) पात्र CPSE को नवरत्न का दर्जा देता है।
- नवरत्न दर्जे के लिए पात्रता मानदंड:
  - सकारात्मक निवल मूल्य वाला मिनीरत्न-I CPSE हो।
  - पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" MoU रेटिंग प्राप्त करना।
  - शुद्ध लाभ, निवल मूल्य और जनशक्ति लागत जैसे प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर 60+ अंक प्राप्त करना।
  - इसके बोर्ड में कम से कम चार स्वतंत्र निदेशक हों।

फर्मों को नवरत्न दर्जे का लाभ

- **बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता:** वे सरकार की मंजूरी के बिना ₹1,000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकते हैं।
- **परिचालन स्वतंत्रता:** घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक गठबंधन, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के गठन में लचीलापन बढ़ा।
- **बढ़ी हुई बाजार विश्वसनीयता:** कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को मजबूत करती है, जिससे कंपनी निवेशकों, भागीदारों और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती है।

- **रणनीतिक निर्णय लेना:** पूँजीगत व्यय, विलय, अधिग्रहण और मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक शक्ति.

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम(IRCTC)

- **परिचय:**
  - IRCTC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकट निर्माण, खानपान और पर्यटन सेवाएँ प्रदान करता है।
- **स्थापना एवं मंत्रालय:**
  - **स्थापना:** 1999
  - **संचालन:** रेल मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) के बारे में

- **परिचय:**
  - IRFC भारतीय रेलवे की समर्पित वित्तपोषण शाखा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य घरेलू और विदेशी पूँजी बाजारों से धन एकत्रित करना है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:**
  - रेल मंत्रालय, भारत सरकार।
- **कार्य:**
  - यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC – ND-SI) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-IFC) के रूप में कार्य करती है।
  - इसके मुख्य व्यवसाय मॉडल में धन उधार लेना और फिर भारतीय रेलवे को संपत्ति पट्टे पर देना शामिल है।

Source: ET

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाना

समाचार में

- भारत का आयकर विधेयक, 2025 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो देश के कर ढाँचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।
  - U.K., U.S., सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ VDAs को संपत्ति या प्रतिभूतियों के रूप में मानती हैं।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ (VDAs)

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 में खंड 47A की शुरूआत के साथ वित्त अधिनियम, 2022 में VDAs को परिभाषित किया गया था।
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम RBI मामले में उच्चतम न्यायालय ने FATF रिपोर्ट की आभासी मुद्रा (VC) की परिभाषा का उल्लेख किया, इसे एक डिजिटल इकाई के रूप में वर्णित किया जो विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है, लेकिन सरकार द्वारा जारी कानूनी निविदा नहीं है।
- न्यायालय ने VDAs की व्याख्या संपत्ति, वस्तु या भुगतान विधि के रूप में भी की और निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अमूर्त संपत्ति या सामान के रूप में माना जा सकता है।

भारत में VDA कराधान का परिचय

- भारत का आयकर विधेयक, 2025 VDAs (क्रिप्टो संपत्ति, NFTs आदि सहित) को संपत्ति और पूँजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।
- यह भारत को यू.के., ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसी वैश्विक प्रथाओं के साथ जोड़ता है, जहाँ कर उद्देश्यों के लिए VDAs को संपत्ति के रूप में माना जाता है।
- VDAs पर पूँजीगत लाभ प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाएगा।
  - VDAs की बिक्री से होने वाले लाभ पर होल्डिंग अवधि के आधार पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ नियमों के आधार पर कर लगाया जाएगा।

विशेषताएँ

- UAE जैसे कुछ देशों के विपरीत, ट्रांसफ़र से VDA आय पर एक समान 30% कर दर लागू होती है, जिसमें लेनदेन लागत के लिए कोई कटौती नहीं होती है।

- VDA ट्रांसफ़र पर 1% TDS (स्रोत पर कर कटौती) लगाया जाता है, यहाँ तक कि पीयर-टू-पीयर (P2P) लेनदेन के लिए भी।
- TDS छूट सीमा छोटे व्यापारियों के लिए ₹50,000 और अन्य के लिए ₹10,000 है।
- कर अधिकारी नकदी या सोने जैसी संपत्तियों की तरह ही जाँच या कर छापे के दौरान VDA को जब्त कर सकते हैं।
- VDA में कार्य करने वाली संस्थाओं (जैसे एक्सचेंज और वॉलेट प्रदाता) को एक निर्धारित प्रारूप में लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
  - VDA को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे करदाताओं की वित्तीय प्रोफ़ाइल में स्वचालित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित हो सके।

महत्त्व

- VDA लेनदेन की रिपोर्टिंग की आवश्यकता पारदर्शिता बढ़ाती है और कर चोरी को रोकने में मदद करती है, क्योंकि अधिकारी स्रोत पर कर कटौती (TDS) जैसे तंत्रों के माध्यम से बड़े क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं।
- संपत्ति के रूप में VDA पर कराधान अधिक वित्तीय अनुशासन पेश करके निवेश व्यवहार को बदल सकता है, जिससे निवेशकों को व्यापार करने से पहले कर निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- यह विदेशी निवेश और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और यह वैश्विक मंच पर भारत के डिजिटल परिसंपत्ति बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

चुनौतियां

- वर्गीकरण और कराधान में प्रगति के बावजूद, निवेशक संरक्षण, बाजार विनियमन और प्रवर्तन तंत्र में अंतराल हैं।
- 30% कर दर पारंपरिक निवेशों की तुलना में VDAs का व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर अधिक कर का भार डाल सकती है, विशेषतः प्रायः व्यापारियों के लिए।

सुझाव

- VDAs को संपत्ति और पूँजीगत संपत्ति के रूप में मानने का भारत का कदम यू.के. और यू.एस. जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए कानूनी मान्यता और नियामक ढाँचे को बढ़ाता है।
- लेकिन एक सुरक्षित डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय विनियमन, उपभोक्ता अधिकार और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने वाला एक व्यापक नीति ढाँचा आवश्यक है।

Source: TH

बोस धातु

संदर्भ

- चीन और जापान के शोधकर्त्ताओं की एक टीम को इस बात के ठोस संकेत मिले हैं कि नियोबियम डाइसेलेनाइड ($NbSe_2$) बोस धातु बन सकता है।

बोस धातु

- ये वे धातुएँ हैं जो महत्त्वपूर्ण तापमान से नीचे कूपर युग्म बनाती हैं, लेकिन सुपरकंडक्टर में संघनित नहीं होती हैं, जिससे सुपरकंडक्टिविटी के बिना बेहतर चालकता प्राप्त होती है।
- सुपरकंडक्टिविटी एक ऐसी घटना है जहाँ एक पदार्थ महत्त्वपूर्ण तापमान से नीचे शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।
- **कूपर युग्म:** इलेक्ट्रॉन आकर्षक बलों के कारण युग्म बनाते हैं, लेकिन लंबी दूरी की सुपरकंडक्टिंग सुसंगतता स्थापित नहीं करते हैं।
- पारंपरिक सिद्धांत भविष्यवाणी करते हैं कि अव्यवस्थित धातुओं को पूर्ण शून्य पर या तो इन्सुलेटर या सुपरकंडक्टर बनना चाहिए, लेकिन बोस धातुएँ शून्य और अनंत के बीच चालकता प्रदर्शित करती हैं।
- **अनुप्रयोग:**
  - **क्वांटम कंप्यूटिंग:** बोस धातुएँ नई क्वांटम अवस्थाओं का पता लगाने में सहायता कर सकती

हैं, और क्वांटम बिट्स (क्यूबिट) के विकास में सहायता कर सकती हैं।

- **संघनित पदार्थ अनुसंधान:** क्वांटम चरणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और अव्यवस्थित धातुओं और जटिल सामग्रियों का अध्ययन करने में सहायता करता है।
- **उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स:** अद्वितीय प्रवाहकीय गुणों वाले अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिज़ाइन को प्रभावित कर सकता है।
- **अतिचालकता अनुसंधान:** बोस धातुएँ अतिचालकता में परिवर्तन को समझने के लिए एक मध्यवर्ती चरण के रूप में कार्य करती हैं, जिससे उच्च तापमान वाले अतिचालकों में सुधार होने की संभावना है।

बोस धातु की सीमाएँ

- **अभी तक कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं:** कोई प्रत्यक्ष औद्योगिक उपयोग नहीं वाली सैद्धांतिक अवधारणा।
- **प्रायोगिक चुनौतियाँ:** तापमान, सामग्री की मोटाई और चुंबकीय क्षेत्रों पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- **अस्पष्ट परिभाषा:** इस बात पर परिचर्चा कि क्या वे अलग-अलग क्वांटम अवस्थाएँ हैं या संक्रमणकालीन चरण।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

भारत को जाम्बिया में तांबा अन्वेषण ब्लॉक मिला

संदर्भ

- भारत ने जाम्बिया में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए 9,000 वर्ग किलोमीटर का अन्वेषण ब्लॉक प्राप्त किया है।
  - जाम्बिया विश्व स्तर पर 7वाँ सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है।

वैश्विक तांबा बाजार में हालिया प्रवृति

- ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तांबा अयस्क की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।
- चीन वैश्विक तांबा गलाने और शोधन क्षमता के 50% को नियंत्रित करता है।
- EV बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के कारण तांबे की माँग बढ़ रही है।
- चिली, पेरू, चीन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक तांबा उत्पादन में अग्रणी हैं।
- भारत, चीन और अमेरिका तांबे की आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे आगामी दशक में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

भारत की तांबे की स्थिति

- 2023-24 में घरेलू अयस्क उत्पादन 3.78 मिलियन टन (2018-19 से 8% कम) था।
  - भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है।
- **भारत में तांबे की खदानें:**

- **तांबे का आयात:** भारत का तांबा सांद्र आयात 2018-19 से दोगुना होकर 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपये हो गया है।

- **घरेलू भंडारों से जुड़ी चुनौतियाँ:** भारत में तांबे के बड़े भंडार हैं, लेकिन खनन से पहले उन्हें व्यापक अन्वेषण की आवश्यकता है।
  - तांबे की खदान को चालू करने का वैश्विक औसत समय 17 वर्ष है।
- **विदेशी निवेश रणनीति:** भारत अल्पकालिक मांग के लिए जाम्बिया, चिली और DRC में तांबे की संपत्ति सुरक्षित कर रहा है।
  - हालाँकि, विदेशी निवेश में महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक जोखिम होते हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिजों में अफ्रीका की बढ़ती हिस्सेदारी

- यह महाद्वीप वैश्विक कोबाल्ट का 70% और वैश्विक तांबे का 16% उत्पादन करता है।
- 2030 तक DRC विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा आपूर्तिकर्त्ता बनने के लिए तैयार है।
- अफ्रीका में भारत के प्रयास: भारत का खान मंत्रालय महत्त्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए DRC , तंजानिया, मोजाम्बिक और रवांडा में कार्य कर रहा है।

Source: IE

स्वावलंबिनी

संदर्भ

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी लॉन्च किया।

परिचय

- स्वावलंबिनी का उद्देश्य युवा महिलाओं के लिए एक संरचित और चरणबद्ध उद्यमशीलता यात्रा स्थापित करना है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में युवा महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की भावना को पोषित करना है, ताकि उन्हें अपने उद्यमों को सफलतापूर्वक बनाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक मानसिकता, संसाधन एवं परामर्श प्रदान किया जा सके।

स्वावलंबिनी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- **संकाय विकास कार्यक्रम (FDP):** स्वावलंबिनी पाँच दिवसीय प्रशिक्षण सत्रों के साथ भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **मेंटरशिप:** एक बार जब प्रतिभागी अपनी व्यावसायिक योजनाएँ बना लेते हैं, तो उन्हें उद्योग विशेषज्ञों और सफल उद्यमियों से मेंटरशिप मिलती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
  - सरकारी योजनाओं और निजी निवेशकों के माध्यम से वित्तपोषण के अवसरों तक पहुँच।
  - स्थापित व्यापारिक नेताओं और पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग के अवसर।
- **महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP):** EDP में रखी गई नींव पर निर्माण करते हुए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) निम्नलिखित की गहरी समझ प्रदान करता है:
  - व्यावसायिक योजना, नेतृत्व और निर्णय लेने का कौशल,
  - वित्तीय साक्षरता और निवेश रणनीतियाँ।
  - बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण।

Source: PIB

समानता का सिद्धांत (Doctrine of Equality)

समाचार में

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा के लिए अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता।

उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय

- न्यायालय ने समावेशिता और समानता के सिद्धांत पर बल दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 में गैर-भेदभाव के आधार के रूप में 'विकलांगता' को भी जोड़ा जाना चाहिए।

- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी अप्रत्यक्ष भेदभाव, जैसे कठोर कट-ऑफ या प्रक्रियात्मक बाधाएँ, जो विकलांग व्यक्तियों (PwD) को न्यायिक सेवा से बाहर रखती हैं, को समानता सुनिश्चित करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।

भारत में समानता का अधिकार

- अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
  - **अनुच्छेद 14** - यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और भारत में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे आधारों पर भेदभाव किए बिना सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है।
  - **अनुच्छेद 15** - यह राज्य द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
    - महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और SCs/STs के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
    - दुकानों, रेस्तरां और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है।
  - **अनुच्छेद 16** - यह सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में भेदभाव को रोकता है।
  - **अनुच्छेद 17** - यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।
  - **अनुच्छेद 18** - यह राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं के अतिरिक्त अन्य उपाधियाँ देने से रोकता है।

Source:TH

अमेरिका ने क्रिप्टो रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की घोषणा की

समाचार में

- अमेरिकी सरकार ने क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व के निर्माण की घोषणा की है।

क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है?

- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व डिजिटल परिसंपत्तियों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसे संघीय विनियामक ढाँचे के अंतर्गत प्रबंधित किया जाएगा।
- **रिजर्व में पाँच प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी शामिल होंगी:** बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, सोलाना और कार्डानो।
- इस पहल का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिकी वित्तीय बुनियादी ढाँचे में एकीकृत करना है।

पहल का महत्त्व

- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व की स्थापना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के समान है।
- डिजिटल संपत्ति रखने से, अमेरिका वित्तीय जोखिमों को कम कर सकता है और अपने आर्थिक पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकता है।
- क्रिप्टोकरेंसी मुद्रास्फीति और पारंपरिक बाजार में उतार-चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य कर सकती है।

Source: TH

फे रिहाइड्राइट

संदर्भ

- नासा और ESA के एक अध्ययन से पता चलता है कि मंगल ग्रह का लाल रंग फेरिहाइड्राइट से उत्पन्न होता है।

परिचय

- **फेरिहाइड्राइट का निर्माण:** फेरिहाइड्राइट के निर्माण के लिए शीत जल की आवश्यकता होती है, जो दर्शाता है कि मंगल ग्रह पर अतीत में तरल जल रहा होगा।
  - ऐसा माना जाता है कि अरबों वर्षों में शुष्क परिस्थितियों में धीमी गति से ऑक्सीकरण के कारण मंगल ग्रह लाल हो गया था।

Comparison of Martian Iron Oxides

Iron Oxide Type	Formation Process	Presence of Water	Implications for Mars's History
Haematite	Oxidation in dry conditions over billions of years	No	Mars rusted gradually, post-water era
Ferrihydrite	Rapid formation in cool water	Yes	Mars rusted much earlier during a wet period

- **जीवन-क्षमता के लिए निहितार्थ:** फेरिहाइड्राइट की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन-क्षमता रही होगी, तथा वहाँ तरल जल की मौजूदगी भी रही होगी।

अध्ययन का महत्त्व

- **जल के साक्ष्य:** फेरिहाइड्राइट की उपस्थिति लंबे समय तक जल की गतिविधि को इंगित करती है।
- **पिछली निवास-क्षमता:** जीवन को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण का सुझाव देती है।
- **जलवायु अंतर्दृष्टि:** गीले ग्रह से शुष्क ग्रह में मंगल के संक्रमण को फिर से बनाने में सहायता करती है।

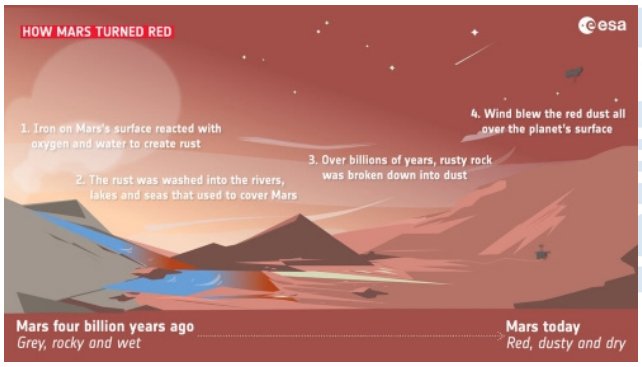

मंगल ग्रह के बारे में

- मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है और इसका रंग लाल है तथा इसके दो असामान्य चंद्रमा हैं।
  - फोबोस: मंगल से ~6000 किमी ऊपर; डेमोस: मंगल से ~20 000 किमी ऊपर।
- इसका वायुमंडल बहुत पतला है, लेकिन धूल भरा है।
- **गुरुत्वाकर्षण:** 3.711 मीटर/सेकंड2 (पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग एक तिहाई)
- मंगल ग्रह पर सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी भी हैं, जिनमें से एक ओलंपस मॉन्स है।
- वायुमंडल: 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.13% ऑक्सीजन

Source: ET

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के मुख्य परिणाम

- देश की प्रथम नदी डॉल्फिन के आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की गई।
  - 8 राज्यों की 28 नदियों में 6,327 नदी डॉल्फिन दर्ज की गईं।
  - उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन हैं, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है।
- वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन केंद्र के लिए जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए, कोयंबटूर के SACON (सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र) में भारतीय वन्यजीव संस्थान के परिसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  - संघर्ष शमन के लिए प्रौद्योगिकी से लैस त्वरित प्रतिक्रिया दल होंगे।
- गांधीसागर अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और बन्नी घास के मैदानों (गुजरात) में चीतों को लाने की योजना है ताकि पुन: प्रवेश प्रयासों को मजबूत किया जा सके।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

- **स्थापना:** 2022 में पुनर्गठित (1952 में गठित पहले भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जगह)।
- **नेतृत्व:**
  - **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री (पदेन)।
  - **उपाध्यक्ष:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (MoEFCC)।
- **संरचना:**
  - 47 सदस्यीय समिति में सरकारी अधिकारी, संरक्षणवादी, पारिस्थितिकीविद, पर्यावरणविद और सैन्यकर्मी शामिल हैं।

- **NBWL से अनुमोदन निम्न के लिए आवश्यक है:**
  - पर्यटक लॉज का निर्माण।
  - संरक्षित क्षेत्र (PA) की सीमाओं में परिवर्तन।
  - वन्यजीव आवास का विनाश/विचलन।
  - टाइगर रिजर्व की अधिसूचना रद्द करना।

गिर राष्ट्रीय उद्यान

- **स्थान:** गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है।
- **स्थापना:** 1965 में, एक अभयारण्य के रूप में, और बाद में 1975 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया।
- यह अफ्रीका के बाहर विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ शेर को उसके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है।
  - 1960 के दशक के उत्तरार्ध से, एशियाई शेरों की संख्या 200 से कम से बढ़कर 674 (जनगणना 2020) हो गई है।
- गिर स्तनधारियों की 40 प्रजातियों और पक्षियों की 425 प्रजातियों का आवास है।

Source: TOI

भारत में नदी डॉल्फ़िन का प्रथम व्यापक अनुमान

समाचार में

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020 में लॉन्च) के अंतर्गत आयोजित नदी डॉल्फ़िन पर भारत का प्रथम व्यापक सर्वेक्षण, मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में 6,327 डॉल्फ़िन की जनसंख्या का अनुमान लगाता है।

मुख्य निष्कर्ष

- भारत मीठे पानी की डॉल्फ़िन की दो प्रजातियों का आवास है: गंगा (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) और सिंधु (प्लैटनिस्टा माइनर)।
- गंगा नदी में 6,324 डॉल्फ़िन और सिंधु नदी में तीन डॉल्फ़िन हैं।
- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है।

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका)

- **विशेषताएँ:**
  - कार्यात्मक रूप से अंधा; शिकार के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करता है।
  - साँस लेते समय होने वाली ध्वनि के कारण इसे सुसु के नाम से जाना जाता है।
  - विशेष रूप से स्वच्छ जल की प्रजातियाँ, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में निवास करती हैं।

- **खतरे:** आवास विनाश, प्रदूषण और शिकार।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
  - CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन): परिशिष्ट I
  - CMS (प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन): परिशिष्ट I
  - IUCN लाल सूची: लुप्तप्राय
- **राष्ट्रीय और राज्य मान्यता:**
  - 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया।
  - असम के राज्य जलीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सिंधु नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा माइनर)

- **विशेषताएँ:**
  - कार्यात्मक रूप से अंधे, इकोलोकेशन का उपयोग करके नेविगेट करते हैं।
  - स्थानीय रूप से इस क्षेत्र में इसे भूलन कहा जाता है।
  - यह मुख्य रूप से सिंधु नदी प्रणाली (पाकिस्तान) में पाया जाता है, तथा इसकी एक छोटी जनसंख्या भारत की व्यास नदी में भी पाई जाती है।
- **खतरे:** आवास विखंडन, सीमित क्षेत्र, जिससे जनसंख्या अलगाव की ओर अग्रसर होती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
  - CITES: परिशिष्ट I
  - IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
- **राज्य मान्यता:**
  - पंजाब का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- डॉल्फिन की एक और प्रजाति अर्थात् इरावदी डॉल्फिन भारत में ओडिशा के चिल्का झील (एशिया की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील) में पाई जाती है।
- अन्य दो प्रजातियों के विपरीत, इरावदी डॉल्फ़िन अंधी नहीं होती हैं और इनका सिर बल्बनुमा होता है, जिसमें चोंच नहीं होती।
- IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

नदी डॉल्फिन का महत्त्व

- नदी डॉल्फ़िन स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को दर्शाती हैं।
- कार्बन पृथक्करण, बाढ़ विनियमन और जल शोधन में सहायता करती हैं।
- वे मछली की जनसंख्या को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन (सुसु) और सिंधु नदी डॉल्फ़िन (भूलन) कई समुदायों में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व रखती हैं।
- वे स्थायी पर्यटन और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

Source: TH

ऑस्कर

समाचार में

- हाल ही में 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ।

ऑस्कर

- ऑस्कर, जिसे आधिकारिक तौर पर अकादमी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
- इसकी स्थापना सबसे पहले 1929 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा की गई थी
- **श्रेणियाँ:** ऑस्कर में कई तरह की श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म सबसे प्रतिष्ठित है।
  - अन्य प्रमुख पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल हैं।

हाल के पुरस्कारों की प्रमुख विशेषताएँ

- ब्राइटन बीच, न्यूयॉर्क की एक इंडी फिल्म "अनोरा" ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित पांच ऑस्कर जीते।
- यह एक सेक्स वर्कर के बारे में एक नाटक है जो एक रूसी कुलीन वर्ग के बेटे से शादी करती है।
- निर्देशक सीन बेकर ने $6 मिलियन के बजट के साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन जीता।

- मिकी मैडिसन ने अनोरा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, हालाँकि उन्हें पूर्ववर्ती जीत (कोई BAFTA, गोल्डन ग्लोब या SAG नहीं) नहीं मिली।
- एड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिससे वह इस श्रेणी में बिना हार के दो बार जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए।
- **तकनीकी जीत:** द ब्रूटलिस्ट ने विस्टाविज़न के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जीता।
- फ्लो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीतने वाली पहली गैर-संवाद एनिमेटेड फिल्म बन गई।
- पॉल टेज़वेल विकेड के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति बने।

Source :TH